जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 122 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 6 मार्च, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

देश भर में फैली अपनी सम्पत्तियों को समेटना चाहती है, कांग्रेस पार्टी

एआईसीसी में इंदर सिंह सिंगला की अध्यक्षता में एक अलग विभाग का गठन किया गया है, इस मकसद से। सिंगला एआईसीसी में फिलहाल जॉइन्ट कोषाध्यक्ष भी हैं

- सिंगला सांसद, विधायक व मंत्री भी रह चुके हैं, पंजाब में। सिंगला पर हाईकमान का पूरा विश्वास है तथा राज्यों में पार्टी के विभिन्न नेताओं को चुनाव के लिये पैसे भेजने का काम सिंगला चुपचाप कई वर्षों से कर रहे हैं।
- अतः, अब कांग्रेस पार्टी की देश में स्थित सम्पत्तियों पर चल रहे मुकदमों को न्यायालय में लड़ना तथा पार्टी की सम्पत्तियों के रख-रखाव व मरम्मत आदि की जिम्मेवारी, सिंगला पर छोड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
- अब तक इन सम्पत्तियों की देखभाल का काम राहुल के करीबी माने जाने वाले कनिष्क सिंह देख रहे थे। पर, अब एआईसीसी में एक नया विभाग बनाकर, यह जिम्मेवारी इस विभाग को सौंपना इस बात का प्रमाण है कि, अब कांग्रेस पूर्णतया गंभीर है, अपनी सम्पत्तियों का कब्जा ग्रहण कर तथा न्यायालय में इन प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक चल रहे मुकदमों को जीतकर एक ही जगह संगठित करने के बारे में।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। एआईसीसी ने देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में फैली अपनी सम्पत्तियों को समेटने (कन्सॉलिडेशन) का काम शुरु कर दिया है। इनमें से बहुत सी सम्पत्तियाँ जिला-स्तर पर हैं तथा इनमें से कई सम्पत्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि पिछले अनेक वर्षों में, विभिन्न संगठनों और प्रतिष्ठानों ने उन पर गैर-कानूनी रुप से कब्जे कर लिये हैं।

इन सम्पत्तियों के सम्बंध में अदालतों में केस दायर करने तथा उन्हें एआईसीसी के अधिकार में लेने की प्रक्रिया करीब 3 साल पहले शुरु हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस ने इन सम्पत्तियों की व्यवस्था एवं देख-रेख के लिये एआईसीसी में एक पृथक विभाग बना दिया है तथा इंदर सिंह सिंगला, जो एआईसीसी के संयुक्त कोषाध्यक्ष भी हैं, इस विभाग के प्रमुख बनाये गये हैं। इन्दर सिंह सिंगला का पंजाब में अच्छा-खासा नैटवर्क है। वे पंजाब से सांसद, विधायक एवं मंत्री भी रहे हैं। उनके दायित्वों में उन राज्यों तथा वहाँ के पार्टी नेताओं को चुपचाप धनराशि भेजना भी शामिल है, जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे इस काम को चुपचाप तथा पूरी निपुणता के साथ अंजाम देते हैं तथा पार्टी के पैसे का हिसाब-किताब रखते हैं।

अब तक कनिष्क सिंह, जो राहुल गांधी के नजदीक माने जाते हैं, कांग्रेस की सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों तथा उनसे सम्बंधित मुकदमेबाजी के काम को संभाल रहे थे। लेकिन अब पार्टी ने इसके लिये अलग से एक विभाग बना दिया है। इस तथ्य से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी अपनी उन सम्पत्तियों को फिर से हासिल करने के मामले में अब ज्यादा गंभीर हो गई है। ज्ञातव्य है कि मुकदमेबाजी में उलझी ये सम्पत्तियाँ बहुत कीमती हैं।

लखनऊ अदालत ने राहुल गांधी पर 200 रु. जुर्माना लगाया

लखनऊ, 05 मार्च। राजधानी लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन पर यह कार्रवाई लगातार पेशी से गायब रहने पर की है। चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हों। इस तारीख को अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 दिसंबर 2022 को वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। वीर सावरकर

- यह जुर्माना लगातार पेशी से गायब रहने पर लगाया गया है।

को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की, जिसमें बताया गया कि आज, यानी 5 मार्च को राहुल गांधी पूर्व निर्धारित एक विदेशी अतिथि से मुलाकात में व्यस्त होने के चलते कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए उन पर 200 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया और 14 अप्रैल को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया।

'राजीव गांधी शिक्षा की दृष्टि से काफी पैदल थे'

मणि शंकर अय्यर ने एक वीडियो जारी कर यह अजीबो-गरीब टिप्पणी की तथा यह भी कहा कि वे दो बार फेल हुए थे, पहले कैम्ब्रिज में और फिर दोबारा इम्पीरियल कॉलेज लंदन में।

- मणि शंकर अय्यर ने यह सवाल भी उठाया कि शिक्षा की दृष्टि से इतने कमज़ोर व्यक्ति को देश का प्र.मंत्री कैसे बनाया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ने ही मणि शंकर अय्यर को राजनीति में एंट्री दी थी तथा उन पर पूरा विश्वास किया था।
- भाजपा, राजीव के नज़दीकी सलाहकार की इन टिप्पणियों से काफी खुश हैं, क्योंकि अब भाजपा के लिये अपने नेता मोदी की शैक्षणिक योग्यता को मुद्दा बनाने वालों को जवाब देना और आसान हो गया है।
- कांग्रेस ने जरूर अय्यर की टिप्पणियों को फिज़ूल की बात बताया और कहा, अय्यर अब एक कुण्ठित नेता हैं, जिन्हें पार्टी अब काफी समय से महत्व नहीं दे रही है।
- कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा, परीक्षा में फेल होना या उत्तीर्ण होना राजनीति की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, राजीव गांधी राजनीति में देश के सफल नेताओं में सदा गिने जायेंगे, क्योंकि पाँच साल में उन्होंने जो देश के लिये हासिल किया, शायद ही कोई ऐसा कर पाया है या कर पायेगा।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने स्वर्गीय राजीव गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाकर पार्टी को शर्मिंदा कर दिया है, जबकि राजीव गांधी ही अय्यर को राजनीति में लाए थे।

एक वीडियो में अय्यर ने कहा कि कई लोगों ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि राजीव गांधी एक एयरलाइन पायलट थे और दो बार फेल हो चुके थे। अय्यर ने कहा, "राजीव गांधी को शैक्षणिक रूप से संघर्ष करना पड़ा था। वो कैम्ब्रिज तक में फेल हो गए थे, जहाँ पास होना तुलनात्मक रूप से आसान था। फिर वो इम्पीरियल कॉलेज लंदन गए और वहाँ भी फेल हो गए। इस बात को लेकर कई सवाल हैं कि अपने इस अकैडमिक रिकॉर्ड के साथ वे प्रधानमंत्री कैसे बने। इस बात से पर्दा हट जाने दो।"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ट्रम्प की विदेश नीति में स्थायित्व या सिद्धांत नज़र नहीं आ रहा'

इस परिस्थिति में भारत की तत्कालिक चिंता है, कब अमेरिका फिर अपनी विदेश नीति बदलते हुए, पाकिस्तान की ओर झुकने लगेगा

- इसका संकेत अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने दिया, जब उन्होंने पाकिस्तान की प्रशंसा की और आभार जताया, एक कुख्यात आतंकवादी को पकड़ कर अमेरिका को सौंपने के लिए।
- इस आतंकवादी ने, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर वापस जा रही थी, एक भारी बम विस्फोट किया था, जिसमें दर्जनों अफगानी सैनिक व 13 अमेरिकी सैनिक मारे गये थे।
- कांग्रेस में दिये गये भाषण में ट्रम्प ने पाकिस्तान को तो भारी धन्यवाद दिया ही, उसी भाषण में भारत की आलोचना की, भारत द्वारा अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ लगाने की वजह से ।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। कई अन्य देशों की तरह, भारत के भी यूनाईटेड स्टेट्स के साथ मित्रता के दिन खत्म हो गए हैं। कोई भी देश, जिसका अमेरिका के साथ कोई भी लेना-देना है, बहुत अनिश्चित है और उसे अमेरिका के वादों और कमिटमैंट्स में विश्वास नहीं है। ये वादे एक मिनट के नोटिस पर या बिना नोटिस के भी पलटे जा सकते हैं।

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है विदेश नीति में इन परिवर्तनों के कारण अमेरिका-पाकिस्तान के प्रति रणनीतिक झुकाव की पुरानी रणनीति पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्षतिग्रस्त एम.आई. रोड

जयपुर, 5 मार्च। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विधायक अमीन कागज़ी ने राजधानी जयपुर की प्रसिद्ध एम आई रोड का मामला उठाया, जो टूटी-फूटी पड़ी है। कागज़ी ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के तहत यह

- राशि जमा होने के बाद भी मरम्मत नहीं?

मामला उठाते हुए राज्य सरकार से एम आई रोड एवं जौहरी बाजार की टूटी सड़कों की मरम्मत कराने का आग्रह किया, ताकि इन मुख्य बाजारों में लोगों को आने -जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा कि दो साल पहले ही एम आई रोड पर काम हुआ था, लेकिन पेयजल पाइप लाइन डालने के लिए अजमेरी गेट से लेकर गवरमैंट हॉस्टल तक सड़क को खोद दिया गया है और अब सड़क की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग की तरफ से राशि जमा करा देने के बावजूद, इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यू.पी., बिहार, मध्यप्रदेश व राजस्थान की सीटें बढ़ेंगी-संसद में

यह भय दिखाकर स्टालिन ने देश में संसदीय सीटों के "डीलिमिटेशन" को तीस साल टालने की मांग की

- दक्षिण भारत के राज्यों के सर्वदलीय सम्मेलन में तमिलनाडु के मु.मंत्री स्टालिन ने "सर्वसम्मति" से इस मांग का प्रस्ताव पारित करवाया।
- स्टालिन का तर्क था, अगर डीलिमिटेशन होता है, तथा, संसदीय सीटों की संख्या 543 ही रहती है, तो तमिलनाडु की आठ संसदीय सीटें कम हो जायेंगी। अतः सर्वदलीय बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया, कि संविधान में संशोधन करके, यह निर्णय लिया जाये, कि जिस अनुपात में उत्तर भारत के भारी जनसंख्या वाले प्रांतों की सीटें बढ़ेंगी, उसी अनुपात में साउथ इण्डिया के राज्यों की राज्यसभा व लोकसभा सीटों की संख्या भी बढ़ाई जायेंगी।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। आगे के तीन दशकों तक लोकसभा सीटें यथावत बनाये रखने की जोरदार वकालत के बाद, तमिनलाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को प्रस्तावित परिसीमन की कवायद के खिलाफ दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों को लामबंद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि परिसीमन के परिणामस्वरुप भारतीय राजनीति में दक्षिण भारत को अप्रासंगिक कर दिये जाने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि परिसीमन की कवायद दक्षिण भारत को देश की सत्ता की राजनीति में पूरी तरह से उपेक्षित कर देगी, क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है कि परिसीमन के परिणामस्वरुप, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे राज्यों की बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण, उन्हें सीटों की संख्या बढ़ने का लाभ मिल सकता है।

उनके द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग को सम्बोधित करते हुये, उन्होंने परिसीमन की कवायद पर जोरदार प्रहार किये और कहा कि यह साफ तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने दक्षिण भारतीय अन्य राज्यों के नेताओं से इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिये एकजुट होने की अपील की।

स्टालिन की अध्यक्षता में हुई इस सर्वदलीय मीटिंग ने केन्द्र से विधिवत रुप से अनुरोध किया कि 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा की सीटों की संख्या तथा संवैधानिक सीमाएं यथावत रखी जायें। उन्होंने कहा कि 84 वें संविधान संशोधन ने 2026 तक उक्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

किसान नेता डल्लेवाल के अनशन के सौ दिन पूरे हुए

हिसार, 05 मार्च। हरियाणा के हिसार जिले में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के 100 दिन के आमरण अनशन के समर्थन में किसानों ने बुधवार को एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया। यह अनशन जिला सचिवालय और नारनौंद के उप मंडलाधीश कार्यालय के सामने आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा है। किसान आंदोलन की दूसरी लहर 13 फरवरी 2024 से खनौरी बॉर्डर पर

- किसानों का कहना है कि सरकार डल्लेवाल की सेहत की चिंता तो जता रही है पर लिखित वादों से मुकर रही है।

शुरू हुई थी। डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठेहैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) गारंटी कानून को जल्द लागू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार एक तरफ डल्लेवाल की सेहत की चिंता जता रही है। वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए सरकार लंबी तारीखें दे रही है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार अपने लिखित वादों से मुकर रही है। उन्होंने मांग कि अगर सरकार वाकई डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंतित है, तो उन्हें तुरंत किसानों की मांगें पूरी करनी चाहिए।

'अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो या व्यापार युद्ध या किसी और तरह का युद्ध, तो हम अंतिम क्षण तक लड़ने को तैयार हैं'

चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता लिन जियान ने न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में बहुत कड़ा जवाब दिया

- जैसा कि विदित है, अमेरिका ने चीन से अमेरिका को जाने वाली अधिकतर वस्तुओं पर 10 प्रतिशत और टैरिफ लगाने की घोषणा की है।
- साथ ही चीन ने भी प्रत्युत्तर में अमेरिका से चीन को निर्यात किये जा रहे सामानः चिकन, गेहूँ, कपास आदि पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
- चीन की इस आक्रामक जवाबी कार्यवाही की तुलना में भारत का रुख काफी नरम तथा "एडजस्ट" करने का रहा। जैसा कि ज्ञातव्य ही है, अमेरिका 2 अप्रैल से "रैसिप्रोकल टैरिफ" लगाने की घोषणा लागू करने की बात कह ही चुका है। अतः भारत के पास चार सप्ताह से भी कम समय बचा है, अमेरिका द्वारा लगाये गये "टैरिफ" को एडजस्ट" करने के लिये। अगर अमेरिका से भारत को निर्यात किये गये सामान पर भारत ने वर्तमान "टैरिफ" चालू रखा तो अमेरिका भी भारत से अमेरिका को निर्यात वस्तुओं पर उतना ही "टैरिफ" लगायेगा और भारत का व्यापार चौपट हो सकता है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मार्च। शेष विश्व के साथ "टैरिफ वॉर" की अमेरिका की एकतरफा धमकी पर साहसिक प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा है कि अमेरिका चीन से आयातित माल पर टैरिफ बढ़ाने के लिए फैनटैनाइल (एक नशीली ड्रग) का झूठे बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ वॉर हो या ट्रेड वॉर, बीजिंग आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है।"

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मंगलवार को न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। उनसे अमेरिका द्वारा चीनी आयात पर शुल्क में दस प्रतिशत वृद्धि किए जाने पर सवाल किया गया था।

उन्होंने कहा कि फैनटैनाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकन शुल्क बढ़ाने का बहाना मात्र है। हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए हम जो कदम उठाएंगे, वे पूरी तरह वैध और आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में फैनटैनाइल संकट के लिए सिर्फ अमेरिका जिम्मेवार है, कोई और नहीं।

अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की थी कि 2 अप्रैल से "रैसिप्रोकल टैरिफ" लागू हो जाएगा। भारत के पास अमेरिका से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले टैक्स को एडजस्ट करने के बारे में फैसला करने के लिए चार सप्ताह से भी कम समय बचा है।

चीन के मजबूत रुख के मुकाबले मोदी का रुख बहुत ढीला है और लगता है, ट्रम्प का आदेश मानने के लिए वे पूरी तरह झुक गए हैं।

इससे पूर्व लिन जियान ने कहा कि अमेरिका के लोगों के प्रति मानवता पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए हमने कई कदम उठाए और इस मसले से निपटने में अमेरिका की सहायता की है। हमारे प्रयासों को स्वीकारने और मानने की बजाय, अमेरिका ने चीन पर आरोप लगा दिया और टैरिफ बढ़ाने की बात कर अमेरिका चीन को ब्लैकमेल कर रहा है तथा दबाव डाल रहा है। हमने उनकी मदद की, इसके लिए वो हमें दंडित कर रहे हैं। इससे अमेरिका की समस्या हल नहीं होगी और इससे हमारे काउंटर नारकॉटिक्स विचार-विमर्श और सहयोग का महत्व कम हो जाएगा।

चीन के प्रवक्ता ने आगे कहा, "हम धमकियों से डरने वाले नहीं है। डराने-धमकाने की नीति हम पर नहीं चलेगी। दबाव, डर और धमकी चीन से डील करने का सही तरीका नहीं है। अगर अमेरिका सही मायने में फैनटैनाइल मसले को हल करना चाहता है तो चीन के साथ बराबरी के स्तर पर वार्ता की जाए। अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे टैरिफ वॉर हो या ट्रेड वॉर हो या किसी भी प्रकार का वॉर हो, हम आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं।"

सी.एन.एन. के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर शुल्क दस प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के बाद चीन ने यह प्रतिक्रिया दी है।

जवाबी कार्यवाही करते हुए चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सामान, जैसे चिकन, गेहूँ, मक्का और कपास पर टैरिफ 15 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, एक्वैटिक उत्पाद, फल, सब्जी व डेयरी उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है।

अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दो अप्रैल से रैसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।

फरवरी में वॉशिंगटन में ट्रम्प तथा भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देश इस वर्ष अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले भाग पर चर्चा के लिए मान गए थे।

मोदी व ट्रम्प ने मिशन 500 की घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुँचाना है।

नई दिल्ली ने एक कमेटी गठित की है, जो भारत-यूएस ट्रेड पर रैसिप्रोकल टैरिफ के प्रभाव का अध्ययन करेगी। वाणिज्य मंत्रालय की इस कमेटी में कृषि, खाद्य संवर्धन, भारी उद्योग, इलैक्ट्रोनिक्स व आईटी मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

ट्रम्प ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत की उच्च शुल्क दरों की ओर इशारा किया और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बोफोर्स : सीबीआई ने अमेरिका से हर्शमैन को ढूंढने की अपील की

नई दिल्ली, 05 मार्च। बोफोर्स घोटाला मामले से जुड़ी जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अमेरिका को रोगेटरी पत्र भेजा है, जिसमें अमेरिका से निजी जासूस माइकल हर्शमैन को ढूंढ ने और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। ज्ञातव्य है कि माइकल हर्शमैन ने एक न्यूज चैनल पर दावा किया था कि वो 64 बोफोर्स तोप घोटाले की जांच में मदद कर सकता है। भारत में बोफोर्स घोटाला 1980 के

- माइकल हर्शमैन ने एक न्यूज चैनल में दावा किया था कि वह बोफोर्स जांच में मदद कर सकता हैं।

दशक में सामने आया था और दौरान तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर घोटाले के आरोप लगे थे। दिल्ली की अदालत के आदेश पर अक्टूबर 2024 में अमेरिका को रोगेटरी पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पत्र अमेरिकी नागरिक के टीवी इंटरव्यू को जांच का आधार बनाया गया है। प्रशासनिक स्वीकृतियों के कारण इसे पूरा होने में 90 दिन लग सकते हैं। दिल्ली की अदालत ने सीबीआई के आवेदन को स्वीकार किया है। इसके बाद अमेरिका की न्यायिक प्राधिकरण को पत्र भेजा गया है।